[श्री सुरेश पचौरी]

अनुकरणीय और सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत करगे, ऐसा मेरा आपके माध्यम से उनसे आग्रह है ।

इसके अलावा जो वह प्लांट है, वह आज से प्रारंभ किया जा रहा है और उसमें पड़ा जो कोयला है, उसका स्टाक जब खत्म हो जाएगा, तो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । (समय की घंटी) इसके लिए जो कोयला उस प्लांट के लिए नये कोयला का इस्तेमाल किया जाए । जिस कोयला का मैंने जिक्र किया है, उसका इस्तेमाल न किया जाए ताकि जब सी.बी.आई. को यह मामला सौंपा जाए, तो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । (समय की घंटी)

मैंने यह मामला आपके संरक्षण में इसलिए उठाया है कि हमारे प्रखर पूर्व सांसद, डा. रत्नाकर पाण्डेय जी आज इस संसद के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जैसा उन्होंने पत्र में इस चीज को उजागर किया है, तो हम लोगों का यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि हम राजनीतिक पार्टियों के ऊपर उठ कर सी.बी.आई. को सौंपने की सभी लोग समर्थन करें और माननीय मंत्री जी भी जब यहां पर मौजूद हैं, तो वह स्वयं इस प्रकरण का आडिट आडिटर-जनरल से करवायें--ऐसा मेरे निवेदन है ।

मुझे उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सी.बी.आई. के द्वारा की जाएगी, क्योंकि यह सरासर खुला भ्रष्टाचार का मामला बनता है ।

मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक रूप से पहल करेंगे । धन्यवाद ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) अब हम हाफ-एन-आवर डिसकशन लेने जा रहे हैं । . . . (व्यवधान) वह इसके बारे में है, पर वह सूची में आया नहीं है । अभी हाफ-एन-आवर डिसकशन के बाद . . . (व्यवधान)

Mr. Maheshwar Singh is to raise a discussion on points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on the 28th July, 1992 to Starred Question 284.

माफ कीजिए, श्री मूलचंद मीणा जी यह क्वश्चन रेज करेंगे ।

HALF-AN HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 28TH JULY, 1992 TO STARRED QUESTION 284 RE. NUMBER OF VILLAGES AND HARIJAN BASTIS ELECTRIFIED DURING SEVENTH PLAN PERIOD.

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : सर, 28 जुलाई, को क्वश्चन नं0 284 ग्रामीण विद्युतीकरण और हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण से संबंधित था । मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत देश कृषि प्रधान है । वैज्ञानिक तौर तरीकों से कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए कई नई-नई तकनीकें कृषि के विस्तार के लिए इस देश के अंदर लागू की गई । गांव का आदमी पहले बैलों की जोड़ी और एक चमड़े का तरस होता था, उससे सिंचाई किया करता था । उसके बाद इंजन पंप सैट जो डीजल के इंजन होते हैं, इनका प्रयोग करने लगा । इसमें खर्चा ज्यादा आने लगा । बिजली का उत्पादन जैसे-तैसे बढ़ा और गांवों में सिंचाई के कार्य में बिजली की मोटर लगा कर सिंचाई करने से उनको थोड़ी सुविधा मिली और सस्ती सिंचाई होने लगी । इस उद्देश्य को लेकर सरकार ने गांवों में विद्युतीकरण करने की योजना बनाई इस क्वश्चन के अंदर मंत्री जी ने 28 तारीख को यह बताया था कि हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक लाख 506 गांवों को, एक लाख 740 हरिजन बस्तियों को इलैक्ट्रिफाई कर दिया है । सारे आंकड़े जो मंत्री जी ने दिए यह तो तथ्यों से परे हैं और केवल कागजी आंकड़े हैं । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ऐसे गांव भी आंकड़ों के अंदर हैं जिनमें कि बिजली के खंभे

तक गाड़े नहीं गए, बिजली की तारें खींची नहीं गई और बल्ब तक जला नहीं है। वह तो आंकड़े आप दर्शा रहे हैं कि इतने गांवों को हमने इलैक्ट्रिफाइड घोषित कर दिया। जहां तक हरिजन बस्तियों को बिजली देने की बात है तो वह हरिजन बस्तियों के नाम पर जो पैसे वाले थे या जिनकी लाठियों में जोर था, उन लोगों के घरों में जरूर लाइटें लग गई हैं, लेकिन हरिजन बस्तियों में लाइटें नहीं गई हैं। मंत्री जी, आप इसका सर्वे कराएं, जांच कराएं कि कितने ऐसे गांव हैं जिनके अंदर हरिजन बस्तियों में लाइट नहीं गई है जबकि आपके द्वारा यह दर्शाया गया है कि इतनी हरिजन बस्तियों को लाइट दे दी गई है। उदाहरण के तौर पर, मैं सवाई माधोपुर जिले से आता हूं मैं आप के माध्यम से मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले के जो आंकड़े आपने दिए हैं उनमें 50 परसेंट भी ऐसी हरिजन बस्तियां नहीं हैं जिनमें कि लाइट चली गई हो। 50 परसेंट भी लाइट नहीं गई है। मंत्री जी, अधिकारी आपको यह आंकड़े दे देते हैं। आज राजस्थान में बिजली के लिए वहां का किसान तरसता है। उसको बिजली समय पर नहीं मिलती है। जिन गांवों के अंदर बिजली चली गई है उन गांवों में जिन किसानों को बिजली नहीं मिली है वे किसान परेशान हैं। जिन गांवों को इलैक्ट्रिफाइड घोषित नहीं किया है और आपके रेकार्ड के अंदर उनको इलैक्ट्रिफाइड माना गया है उन गांवों के अंदर विद्युत विभाग द्वारा किसानों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा? राजस्थान के अंदर तीन ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समितियों का गठन किया गया था। एक टोडा भीम है सवाई माधोपुर जिले के अंदर, दूसरा सवाई माधोपुर जिले के अंदर महुआ ब्लाक है और तीसरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर कोटपुतली है। उन सहकारी समितियों को ब्लाक की सहकारी समितियां बनाया गया था और उनको उस एरिया का, उन गांवों का सर्वे करा कर उनको पैसा भी, आपका जो विद्युतीकरण बोर्ड है, आपका जो ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड है, जिसने उस स्कीम को पास किया था, उसके माध्यम से मिला था। लेकिन, मेरी समझ में नहीं आता, योजना का सारा सर्वे कराकर आपने जो पैसा दिया ताकि सारे गांव इलैक्ट्रिफाइड हो जायें, वह कहां गया? आपके इन कर्मचारियों और अधिकारियों ने क्या किया? आप देखिए, उन तीनों ब्लाकों में आधे-आधे गांव इलैक्ट्रिफाइड हुए हैं और बाकी आधे-आधे गांव नहीं हुए हैं। पैसा उन सोसायटयों का आपका समाप्त हो गया। आज स्थिति यह है कि राजस्थान का विद्युत बोर्ड उन सोसायटियों को अपने अधीन नहीं मानता और आप जो उनको कर्जा या अनुदान देते थे आपने यह अनुदान या कर्जा देना भी बंद कर दिया। आज उन सहकारी समितियों की, ब्लाकों के किसानों की स्थिति क्या है? वहां डी० पी० छः महीने के बाद लग सकती है, डी० पी० लगती नहीं है, तार टूट गए तो तार लगते नहीं हैं, खम्भे टूट गये तो खंबे लगते नहीं हैं, अगर कोई नए कनेक्शन लेना चाहता है तो उनको मिलते नहीं। ऐसी स्थिति आज उन ब्लाकों के अंदर किसानों की हो रही है। तो मैं एक तो मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति जो हैं, उन्हें या तो आप अनुदान दीजिए या कर्जा दीजिए, लेकिन उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई योजना आप जरूर बनाइए।

दूसरा, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप को उदाहरण देना चाहता हूं कि सवाई-माधोपुर जिले के अंदर 1,046 गांव हैं और इनमें 283 गांव में बिजली नहीं है। आपके आंकड़ों में तो सारे जिले के अंदर बिजली पहुंचाना बताया गया है। मंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कितने गांव हैं और आपने कितने गांव के अंदर बिजली पहुंचाई है? यह सब आंकड़ों से चलने वाला नहीं है। आकड़े तो, जो आप स्कीम पास करते हैं उसके आधार पर, बनाए जाते हैं। वास्तविकता क्या है? यह जानने की जरूरत है। मंत्री जी, आप तो किसान के घर में पैदा हुए हो। आपको तो जानकारी होगी कि किसानों के सामने कैसी दिक्कतें आती हैं, कितना उनको कष्ट उठाना

[श्री मूलचन्द मीणा]

पड़ता है। तो आप वास्तविकता को देखें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब मैं विधानसभा का सदस्य था, जिस क्षेत्र से मैं विधायक था, वहां मैंने देखा किसानों की दुर्गति हो रही है। वहां पन्द्रह गांव के लिए लाइन खींची गई थी। मैंने कई बार राजस्थान सरकार के मंत्री जी से, अधिकारियों से भी कहा कि आपने पांच साल पहले इनकी लाइन जरूर खींची थीं और उस एरिए में आपने तार भी लगाए थे, लेकिन आज वहां एक खंबा नहीं है बिजली का, तार नहीं है और आपकी रिपोर्ट में तो इलेक्ट्रिफाइड हैं। उनका कोई इलाज नहीं है। किसी के सामने जाकर आप कहें तो आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि यह तो इलेक्ट्रिफाइड पहले से ही हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आपने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस-किस प्रांत को कितना-कितना पैसा दिया? और, कितने-कितने गांव की स्कीम आपके सामने, आपके बोर्ड के सामने लाई गई? क्या यह स्कीम पूरी हो गई?...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मीणा जी, एक बात आप सुन लें कि यह हाफ एन ऑवर डिसकसन है, तो आधा घण्टा केवल आप ही का नहीं है।

श्री मूलचन्द मीणा : जी, सर, मैं खतम कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : नहीं, मैं केवल रूल की बात कह दूं। आधे घंटे के अंदर आप भी बोलेंगे, कुछ और माननीय सदस्य भी बोलेंगे और मंत्री महोदय को भी जवाब देना है। इसलिए आप जरा जल्दी खतम कर दीजिए।

श्री मूलचन्द मीणा : बहुत कम बोलूंगा, सर। मंत्री जी, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जहां सिंचाई के लिए कोई नहरें नहीं हैं, केवल एक ही साधन है बिजली और इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप राजस्थान की ओर विशेष ध्यान देते हुए, वहां के किसानों के भले को देखते हुए, वहां सर्वे कराकर या जांच कराकर, बिजली के अधिकारी या राजस्थान गवर्नमेंट किसानों के प्रति निष्क्रिय है इसको ध्यान में रखते हुए, वहां के किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए योजना के रूप में, जो भी उसमें गड़बड़ हुई हो उसको ठीक करते हुए, उनको बिजली दें। यहां तक हरिजन बस्तियों की बात है, हरिजन तो इस दुनिया में सबसे गिरे हुए स्तर का है, उसको ऊपर उठाने की जरूरत है, उनके घरों के अंदर उजाला करने की जरूरत है। मंत्री जी, आप देखें उनको धोखा देकर उनके नाम पर जिन लोगों ने बिजली ली है और जिन लोगों ने दी है, जबकि हरिजनों को नहीं मिल रही है, तो उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। जयहिंद।

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, ग्रामीण विद्युतीकरण और हरिजन बस्ती विद्युतीकरण के संदर्भ में जो प्रश्न श्री शांति त्यागी जी ने इस माननीय सदन में उठाया था और उस संदर्भ में जो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था उससे जो मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, उस पर मुझे चर्चा करने की आपने अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

इससे पूर्व कि मैं अपनी बात कहूं, मैं इस बात पर खेद व्यक्त करना चाहूंगा कि उस दिन जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे तो मंत्री महोदय ने इस प्रकार के आंकड़े इस माननीय सदन में उपस्थित किए कि जो सारे सदन को गुमराह कर सकते हैं, उन्होंने एक आंकड़ों का जाल बिछाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस जाल में वे स्वयं फंस गए हैं। यह मैं कुछ आंकड़े देकर सिद्ध करूंगा।

"क" भाग में सदस्य महोदय ने यह जानना चाहा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में देशभर में कितने गांवों का

विद्युतीकरण हुआ और कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हुआ है? मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा कि 1,00,740 हरिजन बस्तियों और 1,00,506 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। इसी संदर्भ में जब 3 अगस्त को लोक सभा में प्रश्न पूछा गया, दूसरे सदन में प्रश्न पूछा गया तो वहां पर... **(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्य को मैं यह कहना चाहता हूं कि लोक सभा में क्या पूछा गया, क्या कहा गया, वे उसका उदाहरण दे रहे हैं, उसका उदाहरण राज्य सभा में नहीं दिया जा सकता।

श्री महेश्वर सिंह : नहीं दूंगा, सारी सर। जो दूसरे सदन में प्रश्न पूछा गया, उसमें मंत्री महोदय ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें यह कहा गया कि 4,87,000 ... **(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : नहीं, यह भी नहीं कहिए। दूसरे सदन की बात नहीं कहें।

श्री महेश्वर सिंह : इसी संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया... **(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : हां। कहिए कि इस संदर्भ में।

श्री महेश्वर सिंह : ठीक है सर। मंत्री महोदय तो यहीं थे वहां भी।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): The figures given by the Minister can be quoted.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Reply can be quoted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Only reply can be quoted.

श्री महेश्वर सिंह : रिप्लाई क्वोट कर रहा हूं। मंत्री महोदय ने इसी संदर्भ के एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 4,87,508 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। अब मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब यह 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात कहते हैं तो 1,00,506 गांवों की बात कहते हैं और उसके बाद यह कहते हैं कि 4,87,508 गांवों का विद्युतीकरण हो गया। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो 3,87,002 गांव हैं, क्या इनका सारा विद्युतीकरण 7वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद और दो वर्षों में हो गया?

इसी प्रकार एक सप्लीमेंटरी जब मंत्री महोदय से यहां पूछा गया तो उसके उत्तर में उन्होंने यह कह दिया कि देशभर में कुल गांव 5,00,890 हैं और जो गांव अभी शेष बचते हैं इलैक्ट्रीफिकेशन के लिए, उनकी संख्या उन्होंने 92,000 बतलाई। इसी संदर्भ में जब एक प्रश्न पूछा गया तो कुल गांवों की संख्या 5,79,132 बतलाई गई और वहां भी कुल गांव जो शेष रह गये उनकी संख्या 91,624 बतलाई गई। मैं यह जानना चाहूंगा कि केवल 15 दिनों में यह 10,000 गांवों की उत्पत्ति कहां से हो गई? इन आंकड़ों में यह अंतर क्यों है? और इसके बाद जो ऊर्जा विभाग की नेन्युअल रिपोर्ट है, उनका यह कहना है कि अभी देशभर में लगभग 1,00,000 गांव विद्युतीकरण के शेष हैं। अब मंत्री जी का कहना है कि केवल 92,000 शेष हैं या 90,000 शेष हैं और ऊर्जा विभाग का कहना है कि 1,00,000 शेष हैं। तो यह भी स्पष्टीकरण मंत्री महोदय दें कि इनमें से कौन से आंकड़े दुरुस्त हैं?

अब जहां तक हरिजन बस्तियों का संबंध है, जो विभाग की एन्युअल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 31-01-91 तक जो हरिजन बस्तियां इलक्ट्रीफाइड हुई हैं उनकी संख्या 2,45,583 बतलाई गई है और मंत्री महोदय का कहना है कि 1,00,740 हरिजन बस्तियां इलैक्ट्रिफाइड हुई हैं। तो मंत्री महोदय बतलायें कि कौन से आंकड़े ठीक हैं? क्या जो ऊर्जा विभाग के आंकड़े हैं एन्युअल रिपोर्ट में, वे दुरुस्त हैं या जो इस माननीय सदन में मंत्री महोदय ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे दुरुस्त हैं?

अब जहां तक ट्राइबल एरिया की बात है, एन्युअल रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश भर में 1,11,886 गांव हैं, और जो इलैक्ट्रिफाइड हुए हैं वह 73532 हैं।

[श्री महेश्वर सिंह]

जब यहां एक सप्लीमेंट्री पूछा गया था तो मंत्री महोदय ने राजनीतिक तौर से यू० पी० की सरकार को बीच में खींचना चाहा । उन्होंने यह कह दिया कि विद्युतीकरण में यू०पी० अभी बहुत पीछे है और 70,000 गांव अभी शेष हैं, जहां कि बिजली नहीं पहुंच पाई है । लेकिन आपके विभाग की जो एन्युअल रिपोर्ट है, वह कहती है कि केवल 29622 गांव शेष हैं । इनमें कौन से आंकडे शुद्ध हैं ? आपने कह दिया 70,000 और विभाग का कहना है –29,622 हैं । आपने मध्य प्रदेश की सरकार को भी खींचना चाहा । मध्य प्रदेश के बारे में जो एन्युअल रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6449 गांव शेष हैं और आपने यहां जो आंकडे रखे हैं, उसके मुताबिक 8000 गांव शेष है । जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, इस संदर्भ में आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वहां शतप्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है । उसमें आपने हिमाचल प्रदेश के कुल गांवों की संख्या 16807 बतलाई है और इसमें 485 गांव जन जातीय के बतलाए हैं और फिर अपने उत्तर में यह भी स्वीकार किया है कि अभी 46 गांव शेष हैं । लेकिन इन 46 गांवों का विद्युतीकरण संभव ही नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने चाहे कोई भी आंकड़े प्रस्तुत किए हों, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जब मंत्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देंगे तो या तो वह आज ही स्पष्ट करें कि कौन से आंकड़े ठीक हैं, या बाद में इन आकडों का पूरा ब्यौरा लिखकर दें । लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसा मीणा जी ने यहां कहा कि चाहे किसी भी प्रांत के आकड़े हों, अगर एक भी गांव के आधे घरों में बिजली पहुंच गई हो तो उनका शतप्रतिशत विद्युतीकरण बतलाया गया है और इसलिए यह सारी गड़बड़ी हुई है और जहां तक हिमाचल प्रदेश का संबंध है, यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस के जमाने में मुख्य मंत्री महोदय ने हिमाचल दिवस पर एक एलान कर दिया कि हिमाचल में कोई भी गांव अब ऐसा नहीं है जहां पर बिजली नहीं है, जिसका परिणाम आज हमको भुगतना पड़ रहा है ।

आर० ई० सी० निगम की स्थापना 1966 में की गई थी । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब से इस निगम की स्थापना हुई है, ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी आई है । लेकिन जो आकड़े दिए हैं उससे भी मैं सहमत नहीं हूं । इनका कहना है कि 1968 तक केवल मात्र 12 प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ था और अब 82 प्रतिशत हो गया । यह 82 प्रतिशत केवलमात्र कागजों में हैं । आज जब आर०ई०सी० निगम के पास कोई भी स्कीम जाती है तो कभी एक बहाना, कभी एक ओब्जेक्शन तो कभी दूसरा ओब्जेक्शन लगकर वापिस आ रही है । इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह नम्र निवेदन है कि दोबारा इस चीज का सर्वेक्षण किया जाए कि कितनी हरिजन बस्तियां बकाया हैं, कितने गांव बकाया हैं और इसके सही आंकड़े सदन में प्रस्तुत किए जाएं । इसके अतिरिक्त जहां तक आर० ई०सी० की कारगुजारी है –(घंटी)– मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करुंगा, उपसभाध्यक्ष जी । आज आर० ई०सी० ने स्कीमों को स्वीकृत करने के लिए जो मापदंड रखे हैं, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है । आप इस बात से सहमत होंगे कि विशेषकर पहाड़ी प्रांतों में बिखरी हुई आबादी है, वहां की भौगोलिक स्थिति बहुत कठिन है और वहां जो मैदानी इलाकों के लिए आंकड़े हैं उनके आधार पर विद्युतीकरण नहीं हो सकता । चूंकि वहां चार गांव एक जगह हैं और चार गांव छः किलोमीटर पर हैं और एक घर से दूसरे घर तक बिजली ले जाने के लिए पोलों का खर्चा भी ज्यादा आता है । अगर कम पोल लगेंगे तो ट्रांसमीशन लॉस होगा और जो ट्रांसफारमर्स के लिए आपने एक मापदण्ड रखा है कि जितनी उसकी केपेसिटी है उतने घर कवर होने ही चाहिए । पहाड़ों में यह मापदंड नहीं चल सकता, क्योंकि वहां पर बिखरी हुई आबादी है । जितनी आप लम्बी लाईन खीचेंगे, जितनी पोलों की दूरी रहेगी उतना ट्रांसमीशन लॉसेज

होगी । इसलिए इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और कुछ छूट दी जाए । इसका आधार आबादी पर न रखा जाए, बल्कि जगह की भौगोलिक परिस्थिति को आधार रखा जाए । मंत्री महोदय ने यह भी स्वीकार किया है कि आने वाले समय में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी । एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह कहा है कि 1996-97 में बिजली की जो आवश्यकता देश में हो जाएगी वह 4,16,274 मिलियन यूनिट हो जाएगी। तो उसका सीधा अर्थ यह है कि बिजली उत्पादन की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा । आज भारत में बिजली के सोर्सेज की कमी नहीं है बल्कि रिसोर्सेज की कमी है । उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि थर्मल बिजली का संबंध है, थर्मल से पैदा की गई बिजली मंहगी पड़ती है और जो हाईडिल प्रोजेक्ट द्वारा बिजली पैदा की जाती है वह सस्ती पड़ती है । पहले जो हाइड्रो विद्युत इंस्टाल्ड कैपेसिटी थी और जो आपकी थर्मल विद्युत इस्टाल्ड केपेसिटी है, उसका अनुपात 40 और 60 था । आज वह 28 और 72 हो गया है अर्थात् सरकार ज्यादा ध्यान आज थर्मल की ओर दे रही है और हाईडिल प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रही है । फलस्वरूप जो बिजली आज पैदा हो रही है वह महंगी है, उसको कॉस्ट आफ जनरेशन ज्यादा है ।

इसलिए मैं अंत में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि थर्मल के बजाय हाईडिल प्रोजक्ट की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। हिमाचल प्रदेश मात्र एक ऐसा प्रदेश है जो 20000 मैगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है लेकिन सीमित साधन होने के फलस्वरूप केवल 3200 मैगावाट ही बिजली पैदा हो रही है। इससे ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए हिमाचल की सरकार प्रयत्नशील है । प्राइवेट सैक्टर में लोगों को आमंत्रित करे या विभिन्न प्रांतों की सरकारों के साथ मिलकर विद्युतीकरण का काम करे, अपने स्रोतों का दोहन करे ।

अंत में मैं एक प्रार्थना आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जितनी बिजली पैदा करने का पोटेंशियल है, उसके लिए जब भी आप विभिन्न योजनाओं को विदेशी आर्थिक सहायता के लिए अनुमोदित करें, तो हिमाचल प्रदेश में लारजो हाईडिल प्रोजेक्ट, पार्वती हाईडिल प्रोजेक्ट आदि का विशेष ध्यान रखें और उनको अनुमोदित करे ताकि अगर भारत सरकार के लिए संभव नहीं है तो विदेशी आर्थिक सहायता उसको मिल सके और देश में बिजली का ज्यादा उत्पादन हो सके ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो फिर से हमको आंकड़ों के जाल में नहीं फंसायेंगे बल्कि सच्ची-सच्ची बातें इस सदन के सामने रखेंगे । इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । धन्यवाद ।

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, rural electrification is a very important and serious issue in the country's overall development. But, unfortunately, it has been continuously ignored by the successive governments. As a body which approves the policies of the Government, you and I are duty-bound to ask the following two questions. Firstly, are the provisions in our Constitution and the Directve Principles of State Policy being adhered to or have the successive governments failed to fulfil the aspirations of a majority of our people? Secondly, are you ready to live in a village with the conditions prevailing there?

There are over thirty million jobseekers in India today. I submit that the present socio-economic unrest can be tackled effectively in a very large measure through creation of more productive jobs in the framework of enhanced rural industrialisation leading to increased GDP and a check on population growth. It is very significant that out of the thirty target

[Dr. Naunihal Singh]

districts identified in the country with very high population growth rates, eighty-three are in the States of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan. It is well known that the size of the family amongst the educated and employed has shown a significant decrease. It is also well known that literacy and mass education are very closely related availability of light, electrical power and energy. Nevertheless, we should also modify the slogan—HUM DO HAMARE DO to HUM DONO EK HAMARA EK. Further, nowhere is the rural-urban divide more glaring than in the area of power consumption. Today, while 23 per cent of Indians in urban and industrial centres consume 75 to 80 per cent of electrical power generated, the rural areas with 77 per cent of our population get only about 20 to 25 per cent. This is why rural development could not be envisaged and this is the resultant reason for the poverty of rural India. For the reason alone, India is listed among the ten poorest countries of the world even after forty-five years of freedom. Surely, our Constitution which guarantees certain rights to each and every Indian, intended to provide equal per capita provisions of energy and power for rural and urban populations. Since this has not been honoured, this was thus a clear violation of the spirit and content of the Constitution of India. Sir, this should be noted and this is a very serious thing. How would you react if the rural youth within a radius of a hundred miles were to converge on the city demanding equal distribution of power, diesel, LPG, kerosene, transport, schools, telephones and other essential inputs necessary for development? It is only too well known that development and per acpita energy consumption are directly related. For example, it is 200 KWH per annum in India vis-a-vis 4,000 KWH per annum in the USA. So, development, industrialisation and availability of energy are inseparable. It, therefore, follows that if the developmental process is to be speeded up in the rural areas, massive dosage of commercial energy, directed at augmenting rural industrialisation, is the only answer.

Sir, one can surely admit that if we want to ensure equal means of livelihood facilities and resources, we will have to ensure that a light is lit and a fan is switched in every rural home when these facilities are being enjoyed in the urban centres. To this end, I would humbly plead for the following changes in the State policy:

(1) Separation of the 210 V domestic power supply network from the HT and 440 V 3-phase supplies to the industrial and agricultural sectors including irrigation.

(2) Authorising every industry, in particular, the sugar, agro-based and other isdustries, in the rural areas to generate, distribute and sell power.

(3) Bringing forward legislation prohibiting burning of bagasse or other agro-residues in the fields as has been done in other countries of the world.

(4) Opening up of the coal industry to private sector participation immediately to increase rapidly the availability coal at least by 50 million tonnes per annum.

(5) Introduction of high-efficien-coal-fired—this is very important—turbo machinery in sugar industry so that decentralised power can be generated and distributed in the rural areas.

(6) Enlarging the concept of workers' participation in management—this is very important—to primary producers' participation in preferential equity of industries

processing their produce and their derivatives.

(7) To end the monopoly of the State Electricity Boards, every industry requiring more than half a MW of power should be made duty-bound to generate, distribute and sell power to its neighbourhood.

All these actions would help in developing abundant power supply for agriculture, for food-processing industries, for education and medical purposes in the rural areas.

Finally, Sir, if the State policies are so changed or modified as envisaged by me, I am pretty sure that it will be an act towards restructuring India, creating a new India, in fact, the real India, which lies in the villages and the dream of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, will be truly fulfilled. Thank you very much, Sir.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष दलित बस्तियों में गरीबों की बस्तियों में विद्युतीकरण का प्रश्न आज एक ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत समस्या है । सरकार कोई भी हो, उस समस्या का निराकरण करने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है ।

मान्यवर, देश के अंदर लाखों नहीं मैं कहती हूं लाखो कि तादाद में बस्तियां हैं गांव हैं और गरीबों के घर तो करोडों की तादाद में होंगे जो अंधेरे हैं और साथ ही जो पोश कालोनियां हैं, धनिक लोगों के घर हैं वहां तो बिजली जगमगा रही है।

लेकिन जो गरीबों की बस्तियाँ हैं, दलितों की बस्तियां हैं उसमें अंधेरा है जिससे बहुत सी समस्यायें पैदा हुई हैं, विकास तो रुकता ही है । अराजकता पैदा होते हैं, समस्यायें पैदा होती हैं, सामाजिक समस्यायें और दूसरी समस्यायें। आज मैं यकीन के साथ कहती हूं कि यह लगभग दो-तीन वर्ष से बिजली के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था विद्युतीकरण की दिशा में होना चाहिए था वह नहीं हुआ । रुका हुआ है । मैं दिल्ली के ही ऐसे बहुत से इलाकों को जानती हूं जहां दो या तीन वर्ष पहले बिजली लगी थी, बिजली के तार लगे थे, तार उखड़ भी गए हैं, पता नहीं सरकार के रिकार्ड में भी हैं या नहीं, बहरहाल वहां बिजली नहीं है । ऐसी बात तो बहुत से नागरिक हमें पहुंचाते हैं । लेकिन मैंने खुद भी कई जगहों पर जाकर देखा है । मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगी कि ऐसी बस्तियों का आप सर्वे कराइए कि पहले सरकार की तरफ से तार लगे या नहीं, विद्युतीकरण का काम हुआ या नहीं ? पर इतना जरूर है कि गरीबों के इलाकों में बजली नहीं पहुच पाई अभी तक । मेरा निवेदन यह है कि क्या आप इसका सर्वे करायेंगे क्योंकि इसमें सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है । नए सिरे से अगर विद्युतीकरण करायेंगे तो उतना ही पैसा फिर लगेगा । मैं यह कहना चाहती हूं कि ऊर्जा मंत्री जी स्वयं उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में बिजली के बारे में मैं क्या कहूं स्वयं मंत्री जी जानते हैं उत्तर प्रदेश की हालत । उपसभाध्यक्ष जी आप भी जब बिहार से आते होंगे रेल से तो उत्तर प्रदेश को अंधेरे में डूबा हुआ पाते होंगे । (व्यवधान) मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहती हूं कि वहां की क्या दुर्दशा है । उत्तर प्रदेश में जनता परेशान है । बिजली मंत्रियों का घेराव करती है । तो बिजली मंत्री परेशान होकर दूसरे शहर में चले जाते हैं । मथुरा में घेराव होता है तो आगरा में चले जाते हैं और आगरा में घेराव होता है तो लखनऊ में चले जाते हैं । सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। जनता परेशान रहती है । अपनी अकर्मण्यता और अक्षमता पर पर्दा डालने के लिए केंद्रीय सरकार पर दोषारोपण करती है । मेरी समझ में नहीं आता कि केंद्रीय सरकार कहां दोषी है । जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है बिजली की उससे पता लगता है कि उत्पादन पहले से ज्यादा हुआ है और उत्तर प्रदेश को भी हिस्सा मिला है। लेकिन होता क्या है ? वहां वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है । जहां पर मंत्रियों

[श्रीमती सत्या बहिन]

का अपना स्वार्थ है या जहां पर लोग एयरकंडीशन जगहों पर रहते हैं, बिजली घर में जगमगाती रहे वहां पर बिजली दे दी जाती है । गरीबों के क्षेत्रों में, आम जनता के क्षेत्रों में से बिजली की कटौती कर दी जाती है । वहां यह हालत है । इसके साथ एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की परेशानी से उद्योगपति खत्म हो रहे हैं । उत्तर प्रदेश का विकास रुक रहा है । वहां के उद्योग धंधों की आप अगर सर्वे करायेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी । वहां के लोग छोटे-छोटे कारोबार वाले, बड़े कारोबार वाले चाहे गाजियाबाद में हो, नोएडा में हो, आगरा में हो, कानपुर में हो वे लोग अपना कारोबार छोड़ कर कर्नाटक में चले गए हैं, गुजरात में चले गए हैं या दूसरी जगह चले गए हैं । इसकी वजह यह है कि वहीं पर बिजली नहीं पहुच रही है । तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं । कारोबार की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं । मैं मंत्री महोदय को बहुत संक्षेप में यह कहना चाहती हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जो इतना बड़ा प्रदेश है, इतना विकसित प्रदेश है उसके लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि बिजली नहीं है, वहां बिजली की व्यवस्था करायें ।

उसके लिए यह दुर्भाग्य की बात है । आप बिजली की व्यवस्था करायें और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार सक्षम है, नहीं सुनती है तो हिदायत देना केंद्रीय सरकार का काम है । जो सरकारें काम नहीं करना चाहती हैं, अक्षम हैं, अकर्मण्य है, उनका आप सही मार्ग दर्शन करें और उनको निर्देशित करें । यह बिजली की समस्या ज्वलंत समस्या है, विकास से जुड़ी हुई है । आम जनता की समस्या है । समाज की समस्या है । इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं । खासतौर से उस वक्त जब हमारे बिजली मंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश के हैं तो यह दुर्भाग्य कम से कम उसका नहीं होना चाहिए ।

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): I only want to ask two of three specified questions. In this jubilee year of Quit India Movement, I want to know whether any subsidy is going to be given to the freedom-fighters, Harijans and Adivasis to electrify their houses. My second question is, how many Harijan bastis have been electrified during Dr. Ambedkar's centenary year, State-wise? My third question is, how many Adivasi bastis, specially in the State of Orissa, have been electrified so far? These are my questions.

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Sir, there is hardly any truth in the statistics presented or the statements made by the R.E.C. That is far from the truth, because R.E.C. has no access to a place inside the villages. I know it because I come from a backward State and I know the situation. R.E.C. has no access to the inside of the village and they collect their statistics from outside the village, because they cannot go beyond that point. The Harijans and the Adivasis generally stay in the outskirts of the village and there is no possibility of the electricity reaching them. That is why I would request the officials of the R.E.C. to be very carfeul when they make any statements or give statistics, because I know personally about the working of the R.E.C. and I know that it has no control over distribution. It is the State Government which looks after the distribution through the State Electricity Boards. So my request is that whatever statistics are prepared, these should be prepared carefully.

Unless we give some extra incentive to Harijans or the backward class people, they will not be able to get electricity because they do not have the capacity to pay for it. Electricity is not only to provide light to their houses; it has also got a socio-economic effect. It has a very special impact on the society. When we talk of electrifying Harijan bastis, it is only one or two persons in a village who are able to get electricity because of

reach the poor people. So I leave it to the House to see whether the statistics given by the Government, are reliable or not. I hope the Minister will clarify these points.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राज्य सरकारों की है और वहां के जो राज्य विद्युतीकरण निगम हैं उनकी हुआ करती है । विद्युत के संबंध में यह वार्षिक रिपोर्ट 1990-91 मेरे हाथ में है जिसके अनुसार 1.11 लाख जनजाति गांवों में से मार्च, 1991 तक 72 हजार 344 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

इसका मतलब यह है कि जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पायी । सातवीं जो योजना है, उसमें विद्युत क्षेत्र के लिए इस एनुअल रिपोर्ट के आधार पर 34,273 करोड़ रुपए कि आवंटन किया गया था लेकिन इसकी तुलना में और ज्यादा रुपए खर्च किए गए 37,201 करोड़ रुपए, जो अपने आप में एक प्रकार से इस विभाग की उपलब्धि है । जितना पैसा विद्युतीकरण के लिए आवंटित किया गया था उससे ज्यादा पैसा इस विद्युतीकरण को आवश्यकता और महत्तता को ध्यान में रखते हुए खर्च किया गया, यह कल्पनाथ राय जी की उपलब्धि है । लेकिन नेगेटिव बात जो जाती है वह यह है कि जितने गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिए था, लक्ष्य के आधार पर, वह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया । यानी उपलब्धि जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पायी । जैसे मैंने अपनी बात प्रारंभ की थी, इसकी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हुआ करती है । तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने अपने वांछित लक्ष्य को पूरा नहीं किया है, जितनी उनको उपलब्धि होनी थी वह नहीं हो पायी है । इसमें मैं प्रमुख रूप से, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से संबंधित हूं तो मैं जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के लिए कुल कितना पैसा आवंटित किया गया और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ ? इसके तहत कितने गांव विद्युतीकृत किए गए और जो आपके विद्युतीकरण बोर्ड की योजना हैं, वे एक तहसील को अडाप्ट कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की कितनी तहसीलों को आपने अडाप्ट किया है और जहां शतप्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया गया है, यह मैं जानना चाहूंगा ? क्या आपके पास कोई फीडबैक सिस्टम है ? जितना पैसा आप राज्य सरकारों को ग्रामीण अंचलों में विद्युतीकरण के लिए और विशेष रूप से जो हरिजन बस्तियां हैं, उनकी विद्युतीकरण की जो सुविधा आप राज्यों को देते हैं तो क्या इसके लिए आपके पास कोई फीडबैक सिस्टम है, क्या कोई मानीटरिंग सिस्टम है कि यदि वे वांछित लक्ष्य को नहीं करते हैं तो आप उन पर क्या कार्यवाही करते हैं ? यदि ऐसा कोई मानीटरिंग सिस्टम नहीं है तो क्या आप निकट भविष्य में कोई ऐसा सिस्टम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ऐसा मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

साथ ही मेरा अंतिम सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की अगले तीन सालों में आप कितनी तहसीलों को अडाप्ट करने जा रहे हैं जिनका शतप्रतिशत विद्युतीकरण हो जाय ?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : एक मिनट । सदन से मैं अनुमति चाहूंगा कि कुछ देर के लिए माननीय सदस्य श्री बी० नरायणस्वामी जी को यहां पर बैठने की इजाजत दी जाए ।

आपकी अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : अनुमति है ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री वी नारायणसामी) पीठासीन हुए]

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, सबसे पहले आपका स्वागत है । महोदय अपनी बात को जारी रखते हुए मैं मंत्री महोदय

[श्री सुरेश पचौरी]

से यह जानना चाहता हूं कि जून, 1992 तक मध्य प्रदेश में कितनी हरिजन बस्तियों को रोशनी प्रदान की गयी है और जो 14वें विद्युत सर्वेक्षण समिति का गठन फरवरी, 1989 में किया गया था, क्या उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हो गयी है तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और उन पर कब तक कार्यवाही करने जा रहे हैं ? यदि वह रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो अपनी तरफ से मंत्री जी पहल करके कब तक वह रिपोर्ट लेंगे, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। महोदय, मध्य प्रदेश एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है जहां हरिजन-आदिवासी बहुत ज्यादा संख्या में हैं। क्या मध्य प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर और ज्यादा उसका ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रतिशत बढ़े, इसको दृष्टिगत रखते हुए जो वित्तीय मदद सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गयी थी, उससे अधिक आठवीं पंचवर्षीय योजना में देंगे और यदि देंगे तो वह राशि कितनी होगी ? अभी तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि दी गयी है और उस राशि के अनुपात में उसने कितना विद्युतीकरण किया है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा।

श्री अनन्त राम जायसवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी यह चर्चा सवाल और उसके जवाब से उत्पन्न विषय पर है, यह पूरे बिजली क्षेत्र को कवर नहीं करता है। मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस सवाल तथा जवाब के आधार पर यह चर्चा मांगी गयी है ... उसी तक यह सीमित नहीं है, नम्बर एक चीज। दूसरी चीज यह है कि केवल यह सवाल पूछा गया था कि कितने गांवों का विद्युतिकरण हुआ और कितनी हरिजन बस्तियों का लेकिन यहां इसके साथ देश का सारी स्टेटस के बारे में जानकारी मांगी जाए तो मैं समझता हूं कि वह उस सवाल से संबंधित नहीं है। जैसे यहां पर चर्चा में आया है, उसके लिए तो अलग से सूचना देनी चाहिए, अलग से जानकारी मांगी जानी चाहिए। तीसरी चीज यह है कि अगर इतनी विस्तृत जानकारी कोई चाहता है तो उसके लिए अतारांकित प्रश्न होता है, वह पूछें और मंत्री जी जवाब दे दें कि इस स्टेट में क्या-क्या हालत हैं। लेकिन ओरल सवाल जो आते हैं उनका मतलब है कि किसी महत्वपूर्ण पब्लिक इम्पोर्टेंस के विषय पर वह सवाल किया जा सकता है। जहां तक जवाब का संबंध है महेश्वर सिंह जी ने इसमें यह सूचना मांगी गई थी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने गांवों में हरिजन बस्तियों में बिजली लगी है। उसका जवाब अगर देखेंगे तो यह नहीं है कि अब तक शुरू से ले कर कितने गांवों में बिजली लगी है। यह सवाल नहीं है और न जवाब है। इसमें यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो आप को डिसक्रिपेंसी नजर आई, आपने पूरा शुरू से लेकर अब तक का कवर किया कि इतने गांवों की डिसक्रिपेंसी है जो आप बताते हैं, वह इसमें है **(व्यवधान)**

श्री महेश्वर सिंह : सप्लीमेंटरी का जवाब भी पढ़ लीजिए न। जो उन्होंने जवाब दिया है, उसको पढ़ लें।

श्री अनन्त राम जायसवाल : सवाल पूछा था कि कितने गांवों में बिजली लगी और कितनी हरिजन बस्तियों में बिजली लगी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और जवाब इसमें आया है जो आप ने पढ़ा था कि एक लाख पांच सौ छः गांवों में बिजली लगी और एक लाख सात सौ चालीस हरिजन बस्तियों में बिजली लगी है। तो इसको यह मानना चाहिए कि पूरा शुरू से लेकर अब तक किन-किन गांवों में बिजली लगी। यह खाली सातवीं पंचवर्षीय योजना का है। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभी जानते है कि बिजली किस गांव में लगे, इसके लिए बिजली सलाहकार समिति होती है जिले में और वह बैठती है, तय करती है कि किन-किन गांवों में बिजली लगनी चाहिए। इसको लगाने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की है।

भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । सप्लाई सिस्टम तथा उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी राज्य बिजली बोर्ड की है । वह जवाब इसमें आ गया है । इसलिए इन्हीं सवालों तक हम लोगों को बहस को कनफाइन रखना चाहिये इधर-उधर नहीं जाना चाहिये । इसके साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं ।

श्री महेश्वर सिंह : आपने यह नहीं पढ़ा कि सप्लीमेंटरी के जवाब में मंत्री जी ने क्या कहा ? (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री बो० नरायणसामी): आप बैठिये । आप बैठिये ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : इसलिये हमने कहा था कि अगर विस्तृत जानकारी हो तो इस तरह की डिसक्रिपेंसी आ सकती है क्योंकि जो सवाल आपने पूछा था वह जानकारी दे दी गई है। अगर उसके अतिरिक्त आप और जानकारी लाते हैं तो उसके लिये अतिरिक्त सूचना चाहिए, उसके लिए फ्रेश नोटिस चाहिए ।

श्री महेश्वर सिंह : इस मूल प्रश्न के सप्लीमेंट्री जो हैं उनको पढ़िये (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): No discussion please. The Minister is there to reply.

श्री एस० एस० सुरजेवाला (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं इस सदन के माननीय सदस्य श्री मीगा जी को मुबारकवाद देता हूं जिन्होंने समाज के दबे हुए वर्ग के विषय में आधे घंटे की चर्चा मांगी जो कि बहुत उपयोगी रही है । मैं हरियाणा प्रांत की चर्चा करूंगा । 1983 में इन्दिरा गांधी जी की प्रेरणा से पूरे हरियाणा में हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने का जो कार्य था वह सम्पन्न हुआ । उसके बाद आज हरियाणा में कोई भी ऐसा हरिजन या पिछड़ा वर्ग का घर नहीं है जिसमें एक-एक प्वाइंट नहीं बल्कि कई-कई प्वाइंट बिजली न लगी हो । गांवों में दूसरे घरों की तरह से हरिजन और दूसरे पिछड़े वर्गों के भाई भी आज बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं । उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर बिजली का समाजिक न्याय के लिए, रोजमर्रा की जिन्दगी के लिए, किसानों की खेती के लिए, औद्योगीकरण के लिए, बिजली का रोज का बढ़ता हुआ प्रयोग जो है, इस्तेमाल जो है, उसके कारण बिजली की उत्पादकता जो है वह बहुत कम है । अगर मैं हरियाणा प्रांत की चर्चा करूं तो हरियाणा प्रांत में तमाम बिजली जो हरियाणा के थर्मल, हाइड्रो और सेंट्रल पावर स्टेशन जो हरियाणा का हिस्सा है, वह मिलाकर लगभग 1600 मेघावाट के करीब हरियाणा को आज बिजली मिलती है, उपलब्ध है । हरियाणा को आज ढाई हजार मेवावाट कम से कम बिजली चाहिए, आज की जो हिरयाणा की जरूरत है, समाज के विभिन्न वर्गों की । हरिजन बस्तियों में केवल बिजली लगाने से हरिजन और गरीब को, ग्रामीण लोगों को बिजली मिलने वाली नहीं है जब तक कि बिजली की पैदावार के लिए नए संयंत्र, नए बिजलीघर नहीं लगाए जायेंगे . . (**समय की घंटी**) मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा के हरिजन, इस देश के हरिजन को तभी बिजली मिल सकती है ।

मैं हरियाणा के बारे में अपनी एक बात कहकर समाप्त करूंगा, कि वहां क्यों लोगों को बिजली नहीं मिल रही है । 1982 में यमुना नगर में एक 840 मेगावाट का ताप बिजलीघर लगाने की योजना हमने शुरू की । उसके लिए जमीन भी एक्वायर करवायी, उसके लिए हमारे देश का जो बिजली मंत्रालय है, सी०ई०ए० से, रेलवे से, कोल डिपार्टमेंट से और हर जगह से उसकी मंजूरी मिल चुकी, बहुत पहले, आज से लगभग 8–9 साल पहले और जमीन एक्वायर की जा चुकी है किसान की हजारों एकड़ भूमि, उसके ऊपर आज कालोनी बन चुकी है, साइट आफिस मौजूद है लेकिन मेरे एक सवाल के जवाब में, लिखित सवाल के जवाब में, मंत्री महोदय ने यह बात कही है कि सारी बात होने के बावजूद भी उसके लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है और 10

[श्री एस० एस० सुरजेवाला]

साल पेंडिंग होने के बाद आज भी जो वह योजना है, परियोजना है बिजली की वहीं खड़ी है ।

इसी प्रकार से फरीदाबाद में गैस बैस्ड प्लांट लगाने की योजना–जिसके लिए स्वयं प्रधान मंत्री जी ने फरीदाबाद में आश्वासन दिया था कि वे जल्दी उसकी मंजूरी दिलवाकर उसको लगवायेंगे, उस परियोजना के बारे में भी यह जवाब लिखित रूप से आया है कि उसके लिए भी गैस पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं है । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हरिजन बस्तियों में बिजली देने का और दी हुई बिजली को चालू करने का, बिजली के लट्टू जलाने का, बिजली के पंखे चलाने का सपना तब साकार हो सकता है जब हमारी सरकार जो है पूरी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराए, उन परियोजनाओं को जो सालों साल से लटकती आ रही हैं किसी तरह से मंजूरी दिलवाय । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Md. Salim. Kindly be very brief. Half-an-Hour Discussion has become One-Hour Discussion now.

SHRI MD. SALIM (West Bengal): I can't help.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): But you have to cooperate.

SHRI MD. SALIM: Mr. Vice-Chairman, Sir, you have already made it one hour!

जो हमारे समाज के पिछडे वर्ग हैं उन्हें जो न्यूनतम सुविधा मिलनी चाहिए रोशनी पहुचाने के बारे में, उस बारे में सवाल है । हमारे दूसरे साथी बहुत से विषय पर कह चुके हैं । मैं इसको ज्यादा लम्बा करना नहीं चाहता हूं । लेकिन हमारे देश में कितने गांवों और खासकर हरिजन बस्तियों में बिजली पहुची है, इसके बारे में जो लोक सभा में सरकार बताती है, बाहर भाषण में मंत्री महोदय जो बात करते हैं और राज्य सभा में जो कहते हैं, इन सब में फर्क है । दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां खम्भे लगा दिए गए हैं, तार पहुंचा दिए गए हैं लेकिन बिजली नहीं मिलती । मंत्री महोदय ने उस रोज के जवाब में यह कहा था कि ओवर आल जो शार्ट फाल हमारी बिजली में है, उसके तहत गांवों में बहुत सी जगहों पर हम बिजली दे नहीं पाते हैं । तो यहां प्राथमिकता का सवाल आता है दूसरे तमाम विषयों की तरह विद्युत देने के बारे में भी । गांवों में विद्युत पहुचाने के बारे में जैसा रवैया अपनाते हैं उसमें हमारी प्राथमिकता खो जाती है, वैसे ही हमारा जो शार्ट फाल है तो उसके कारण अक्सर गांवों मे ज्यादा सप्लाई घटा दिया जाता है ।

दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय ने अपने उस रोज के जवाब में यह कहा था कि अभी पैसा इयरमार्क किया गया है फार द सिस्टम इम्प्रूवमेंट स्कीम्स । हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे कि हर इलाके के लिए एक किस्न का सैट नार्म नहीं रह सकता है । मैं सिक्किम में देख चुका हूं । कहते हैं कि पूरे सिक्किम में रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन हो गया है ।

इसके लिए जशन भी मनाया गया, लेकिन मैंने सिक्किम में खुद ऐसे गांव देखे हैं, जहां बिजली नहीं पहुची है अगर आपका नार्म्स यह रहेगा कि पापुलेशन– तो कभी नहीं पहुंचेगा । खास कर हरिजन बस्ती और ट्राइबल लोग जो रिमोट इलाके मे रहते हैं, वहां हम एक नार्म, जैसा प्लेन इलाके में होना चाहिए, वैसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत विस्तृत एरिया में, बहुत दूर-दूर लोग रहते हैं ।

तो आपको नार्म्स बदलने पडेंगे, अगर आप सिस्टम इम्प्रूव करना चाहते हैं । जो बैकवर्ड इलाका है, जो रिमोट इलाका है, खास करके जो हिल्ली एरिया है, पहाडी क्षेत्र में आपको इलाके को लेना पडेगा, शर्त के मुताबिक पापुलेशन को नहीं, क्योंकि वहां कम लोग बहुत दूर-दूर बसते

हैं । तब आप जो ट्राइवल्स हैं, जो हिल्स में गिरिजन रहते हैं उनको आप यह सहूलियत पहुंचा पायेंगे ।

अब सवाल आता है नई नीति के तहत । मंत्री महोदय ने यह कहा है कि स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड जो है, उसकी गांव में बिजली देने की जिम्मेदारी है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप कोयले के बारे में कैश एंड कैरी की बात बोल रहे हैं, जब आपकी नई नीति के अनुसार स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड को जैसे भी हो फायदा दिलाना है, जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो वहां गांव में लोकहित के तहत हो या दूसरी स्कीम के तहत हो, गरीब लोगों को सस्ती बिजली पहुंचाने की जो स्कीम है, वह तो सैक्रिफाइसड् हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा फायदा नहीं है । वहां स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप कह रहे हैं कि आपका बिजली का भाव लाभजनक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा । और इस वक्त गरीब लोग बिजली गांव में आने के बावजूद पैसा नहीं दे पाते, इसलिए वह अपने घर में बिजली नहीं लगा पा रहे हैं । उनको आप कैसे राहत पहुचायेंगे ?

फिर माननीय मंत्री जी ने इसी विषय पर जो लोक सभा में बयान दिया था और राज्य सभा में जो दिया है—दोनों में अन्तर है । लोक सभा में 31 मई को वह जवाब में कहते है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत पहुंचाने के लिए 280246 गाव बाकी हैं, और अभी आकर राज्य सभा में वह कह रहे हैं 28 जुलाई को 72,000 गांव बाकी हैं । तो यह बढ़ कैसे गए ? क्या सरकार कोई अपना रजिस्टर मेनटेन करती है, या जब जैसे आंकडे की जरूरत पड़ी, वैसा आकड़ा वह पेश कर देती है ?

यह मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में कहा । पूरे देश के बारे में मंत्री महोदय ने ऐसा ही बयान दिया है, जिसमें बहुत फर्क है ।

अभी पिछले दिनों ही फाइनेंस मिनिस्टर के जवाब में इस बात को लेकर काफी हंगामा हुआ कि आप दो किस्म के बयान दो सदनों में नहीं दे सकते । अभी इस सावल में भी माननीय मंत्री जी बतायें कि कौन-सा ठीक है ।

श्री मुहम्मद सलीम "मग़रिबी बंगाल": जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनको जो न्यूनतम सुविधा मिलनी चाहिये रोशनी पहुंचने के बारे में इस बारे में सवाल है। हमारे दूसरे साथी बहुत से रोशनियों पर कह चुके हैं। मैं इस को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं लेकिन हमारे देश में कितने गांवों और खास कर हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंची है इसके बारे में जो लोग समझते हैं सरकार बताती है। बाहर भाषण में जो बात करते हैं। मंत्री महोदय जो बात करते हैं और राजेय सभा में जो कहते हैं। उन सब में फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि ऐसे बहुत से गांवों में जहां

†[] Transliteration in Arabic Script.

فارم جیسا پلین علاقہ میں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت واسٹ ایریا میں بہت دور دور تک لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ کو نارمس بدلنے پڑیں گے۔ اگر آپ سسٹم امپروو کرنا چاہتے ہیں جو بیکورڈ علاقہ ہے جو رموٹ علاقہ ہے خاص کر کے جو ہل ایریا ہے پہاڑی اکشیتر میں آپ کو علاقہ کو لینا پڑے گا۔ شرط کے مطابق پاپولیشن کو نہیں۔ کیونکہ وہاں کم لوگ بہت دور دور تک بستے ہیں۔ تب آپ جو ٹرائبلز ہیں جو ہلز میں گریجن رہتے ہیں ان کو آپ بہ سہولت پہنچا پائیں گے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ نئی نیتی کے تحت منتری مہودیہ نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ الیکٹری سٹی بورڈ جو ہے اس کی گاؤں میں بجلی دینے کی ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئلے کے بارے میں کیش اینڈ کیری بول رہے ہیں۔ جب آپ کی نئی نیتی کے انوسار اسٹیٹ الیکٹری سٹی بورڈ کو فائدہ دکھانا ہے جب آپ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں تو وہاں گاؤں میں لوگ ہت کے تحت ہو یا دوسری اسکیم کے تحت ہو۔ یدی لوگوں کو سستی بجلی پہنچانے کی جو اسکیم ہے وہ تو سیکریفائز ہو جائے گی کیونکہ ہمیں زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ وہاں اسٹیٹ الیکٹری سٹی بورڈ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بجلی کا بھاؤ کھمبے پہنچا دیے ہیں۔ تار پہنچا دیے ہیں لیکن بجلی نہیں ملتی۔ ابھی منتری مہودیہ نے اس روز کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اوور آل جو شارٹ فال ہماری بجلی میں ہے اسکے تحت گاؤں میں بہت سی جگہوں پر ہم بجلی دے نہیں پاتے ہیں۔ تو یہاں پر اتھکتا کا سوال ہے دوسرے تمام وشیوں کی طرح ودھت دینے کے بارے میں بھی گاؤں میں ودھت پہنچانے کے بارے میں جیسا رویہ اپناتے ہیں اس میں ہماری پراتھکتا کھو جاتی ہے ویسے ہی ہمارا جو شارٹ فال ہے تو اکثر گاؤں میں اس کو زیادہ کاٹ دیا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ منتری مہودیہ نے اپنے جواب میں یہ کہا تھا اس روز کے جواب میں کہ ابھی پیسہ ایر مارک کیا گیا ہے "فارمڈ سسٹم امپروومنٹ اسکیم" ہمارے دوسرے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک قسم کا سیٹ فارم نہیں رہ سکتا ہے۔ میں سکم میں دیکھ چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پورے سکم میں رورل الیکٹری فیکیشن ہو گیا ہے۔ اس کے لیے جشن بھی منایا گیا۔ لیکن میں نے سکم میں ایسے گاؤں دیکھے ہیں جہاں بجلی نہیں پہنچی ہے اور اگر آپ کا نارمس یہ رہے گا کہ پاپولیشن — تو جہاں خاص کر کے ہر بجن بستی اور ٹرائبل علاقہ میں جو رموٹ علاقہ میں رہتے ہیں وہاں ہم ایک

†[] Transliteration in Arabic Script.

لالٹین جنک کرنے کے لیے بڑھانا پڑے گا اور اس وقت غریب لوگ بجلی لینے کے باوجود پیسہ نہیں دے پاتے اس لیے وہ اپنے گھر میں بجلی نہیں لگا پاتے ہیں ان کو آپ کیسے راحت پہنچا پائیں گے۔

پھر مانیہ منتری جی نے جو لوک سبھا میں بیان دیا تھا اور راجیہ سبھا میں جو دیا ہے لوک سبھا میں ۳۱ مئی کو وہاں جواب میں کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں ودھت پہنچانے کیلئے ۲۸۲۴۶ گاؤں باقی ہیں اور ابھی آکر کے راجیہ سبھا میں وہ کہہ رہے ہیں ۲۸ جولائی کو کہ ۲۰۰ گاؤں باقی ہیں۔ تو یہ بڑھ کیسے گئے کیا سرکار اپنا کوئی رجسٹر مینٹین کرتی ہے یا جب جیسے آنکڑے کی ضرورت پڑی ویسا آنکڑا وہ پیش کر دیتی ہے۔

یہ میں نے صرف اتر پردیش کے بارے میں کہا ہے۔ پورے دیش کے بارے میں منتری مہودیہ نے ایسا ہی بیان دیا ہے جس میں بہت فرق ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی فائیننس منسٹر کے جواب میں اس بات کو لے کر کافی ہنگامہ ہوا کہ آپ دو قسم کے بیان دو سدنوں میں نہیں دے سکتے۔ ابھی اس سوال میں بھی مانیہ منتری جی بتائیں کہ کونسا ٹھیک ہے۔

"ختم شد"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARANASAMY): Dr. Sivaji-not here. Mr. Minister, you will reply.

श्री शिव चरण सिंह : (राजस्थान): मेरा एक प्रश्न है कि राजस्थान में बिजली के प्रोजक्ट के लिए मंजूरी रुकी हुई है। क्योंकि राजस्थान एक डेफिसिट स्टेट है, वहां बिजली का बहुत कम उत्पादन होता है।

तो माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि हमारी स्टेट के बारे में आप... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): This is about rural electrification, not about power projects.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): Respected Vice-Chairman, Sir, as questions on rural electrification have been asked by several Members, I would like to say that rural electrification is a programme of the State Governments. It is funded under the State Plans and also through financial assistance from the Rural Electrification Corporation. The works in all cases are executed by the State Electricity Boards which alone are responsible for reporting the progress to the Central Electricity Authority and the Department of Programme Implementation. If any specific instances of discrepancies are indicated to me by the hon. Members, I will have them looked into.

It is incorrect to question the veracity of statistics in all cases as from 12 States which have achieved cent-per-cent electrification, no complaints of any village not having been electrified though reported electrified, have been received. Theer are however, demands, for load intensification from the States, which is a continuous process. Funds for this purpose are being made available within the allocation provided by the Planning Commission.

The responsibility for proper maintenance and operation of the system also lies with the State Governments, the State Electricity Boards. Most of the complaints relate to post-const-

†[ ]Transliteration in Arabic Script.

[Shri Kalp Nath Rai]

ruction period such as frequent interruptions in supply due to poor maintenance, inadequate supply due to power shortage. Out of 5,79,000 villages, 4,87,000 villages have been electrified up to 31st March, 1992 and 12 States have achieved one hundred per cent electrification. Of the balance villages, over 73,000 villages are in four States of UP, Bihar Orissa and West Bengal, which are reluctant to take up larger programmes due to difficult financial position of the State Electricity Boards, highly unremunerative nature of the left-out programmes due to high capital investment and low load prospects, power shortage, inadequate system support etc. Most of these States are not even able to fully utilise their allocation. U.P., Bihar and West Bengal, in fact, had in the past requested for reduction of targets.

As at the end of March, 1992, about 92,000 villages were left to be electrified. The Eighth Plan proposals stipulated electrification of 50,000 villages and energisation of 25 lakh pump-sets in the country during the Plan period. Efforts will be made to accomplish the programme depending upon the funds allocated by the Planning Commission on year-to-year basis. Incidentally it may be mentioned that targets set for the Seventh Plan have been substantially exceeded.

No separate census of Harijans bastis has been carried out in the country. Of the 25 States, 16 States are reported to have Harijan bastis. As per the Central Electricity Authority, 4,35,000 villages have been electrified in these States as on 31st March, 1992 and electricity has been extended to about 2,49,000 Harijan bastis.

To promote electrification of Harijan bastis, the Rural Electrification Corporation has been extending concessional assistance and has been persuading the State Electricity Boards to take up electrification of Harijan bastis along with the electrification of main villages. As a result of the efforts made to promote electrification of Harijan bastis, 1,07,000 Harijan bastis were electrified during the 7th Plan compared to about 1,04,000 Harijan bastis electrified in all the years prior to the 7th Plan.

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) in the Chair]

The State Electricity Boards are responsible for execution of the works and reporting the progress in regard to electrification of villages and energisation of pump-sets to the Central Electricity Authority, Ministry of Programme Implementation, which reports form the basis of their intimating the progress under Rural Electrification Corporation programmes. The REC on its part besides conducting usual monitorings, carry special monitoring to test-check 10 per cent of the villages electrified during the year. In this connection, we have advised the State Electricity Boards to send the list of the villages electrified in support of the reported progress. The progress of pump-sets is also verified from the ledgers besides spot inspections on random basis. The State Electricity Boards have been requested to send the list of villages electrified to local Block Development Officers or revenue authorities so that the confirmation in this regard is also made by them.

The Corporation is constantly following up the matter with the State Governments for activation/setting up of State/District level Advisory Committees with representations from MPs and MLAs for reviewing the implementation of rural electrification programme and ensuring, among others, that the reported progress of rural electrification is as per ground realities.

As regards ensuring proper utilisation of funds, the REC, except for initial advance, releases funds to the SEBs on reimbursement basis and the final reimbursement under the project is made after verification of the claims. The procedure itself ensures utilisation of the REC funds for the intended purpose. Some hon. Members have asked questions regarding the allocation of funds during the Seventh Five Year Plan. Let me tell them first about the State of Uttar Pradesh. In the Seventh Five Year Plan, Rs. 63 crores was allocated as Plan outlay and Rs. 57 crores only was utilised. Similarly, 15,150 villages were to be electrified by the Government of Uttar Pradesh but only 700 villages were electrified. This is the responsibility of the State Government. The Central Government does not come here. There are two ways where we come into the picture. One is the Plan allocation done by the Planning Commission. The second is the Rural Electrification Corporation which is a lending agency. The State Electricity Boards submit their proposals for electrification of the villages and submit their applications for the loans and REC provides loans. Therefore, the responsibility of electrification is entirely of the State Government.

Regarding Bihar, during the Seventh Five Year Plan, Rs. 11 crores was allocated for rural electrification but only Rs. 67 lakhs was utilised. The remaining money has not been utilised. This is the Plan allocation money. REC have allocated Rs. 208 crores but only Rs. 106 crores was utilised by the Government of Bihar.

The hon. Member, Mr. Suresh Pachouri wanted to know the allocation for the Madhya Pradesh State. The State of Madhya Pradesh was allocated Rs. 24 crores but only Rs. 18,09,00,000 has been utilised. Even the Government of Madhya Pradesh could not utilise the Plan allocation money. As the hon. Member comes from Madhya Pradesh, he should know about it. The Planning Commission have allocated money to the State Government but they did not utilise even that money.

श्री महेश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं सारी चर्चा का, वह फिर हमको आंकड़ों की जगलरी में फंसा रहे हैं । जो मुद्दे हमने उठाए थे, उनके जवाब इनको देना चाहिए, लेकिन हट-हटकर आप वही जवाब दे रहें है और फिर फिगर्स ही दे रहे है। आपने ही ... (**व्यवधान**) ...

SHRI V. NARAYANASAMY: He is explaining the position of the Madhya Pradesh State.

श्री महेश्वर सिंह : एक मिनट, आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए । आप क्यों बीच में बोल रहे हैं

श्री कल्पनाथ राय : क्यों, क्यों नहीं बोलें

श्री महेश्वर सिंह : आप जब मंत्री बनेंगे तो आप जवाब देना । अभी मंत्री जी को जवाब देने दीजिए ... (**व्यवधान**) ...

उपसभाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बारे में इन्होंने सप्लीमेंटरी के जवाब में कहा है कि 72,000 गांव शेष है और ... (**व्यवधान**) ...

श्री कल्पनाथ राय : यह मैंने नहीं कहा ।

श्री महेश्वर सिंह : और महोदय, इसी बारे में जब प्रश्न पूछा गया था... (**व्यवधान**) ... रिकार्ड है यहां । यहां ओन रिकार्ड है ।

श्री कल्पनाथ राय : नहीं, नहीं । मैं आपसे कहा रह हूं, नहीं ।

श्री महेश्वर सिंह : महोदय, इसी एक प्रश्न के उत्तर में 15 दिन पहले यह कहते है कि ... (**व्यवधान**) ...

श्री कल्पनाथ राय : मैंने नहीं कहा है । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री महेश्वर सिंह : कौनसे आंकडे ठीक है ? यह तो आप बता दें । आप फिर एक जादूगरी चल रहे हैं . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने यह नहीं कहा है । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री महेश्वर सिंह : यहां जवाब में है । यह मेरे हाथ में जवाब है । . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : सुनिए, सुनिए, महेश्वर जी । मैं बताऊं बहस की इसमें गुंजाइश नहीं है । . . . **(व्यवधान)** . . . एक मिनट सुन लीजिए । मिस्टर नारायणसामी, प्लीज, वन सेकेंड, आपने कहा कि इन्होंने यह-यह जवाब दे रखा है और मंत्री जी कह रहे है मैंने नहीं कहा है । दोनों सामने है । तो इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है । आपने अपनी बात कही, इन्होंने अपनी कही । आपको इसमें शक है तो चेयरमैन को इसके बारे में अलग पत्र लिखें । . . . **(व्यवधान)** . . .

SHRI KALP NATH RAI: Mr. Vice-Chairman, Sir, you will be surprised to know that the Government of Uttar Pradesh have not paid Rs. 100 crores arrears due to the REC. The Government of Bihar have not paid Rs. 73 crores arrears due to the REC. The Government of West Bengal have not paid Rs. 30 crores arrears due to the REC. The Government of Orissa have not paid Rs. 24 crores arrears due to the REC. The REC is a lending agency. The State Governments submit the estimates and take the money and they have to electrify. But the money they have taken has not been utilised. What can I do for it? As an hon. Member of Parliament, Maheshwar Singhji, you should know who is responsible for electrification. Is the Central Government responsible? It is the responsibility of the State Governments. The money is allocated by the Planning Commission. The State Governments take the money through the REC. The REC was established in 1969 for three purposes; pump energisation, rural electrification and system improving. For these purposes, loans are being given. As you are talking very much of the Harijan 'bastis', let me tell you, the Kutir Jyoti Yojana was started by the Govment of Shri Rajiv Gandhi for the people who are below the poverty line. And, that Yojana was stopped in 1990 by your Government. What should I say about this? Who will be benefited by the Kutir Jyoti Yojana? The people who are below the poverty line. Harijans, Girijans and Adivasis. That scheme was introduced by the Rajiv Gandhi Government and that was stopped in 1990. Who was ruling the country at that time? You better know it. I do not want to mention that.

Mr. Vice-Chairman, Sir, as I have told you, the Government led by Mr. Narasimha Rao is going to introduce the Kutir Jyoti Yojana again. The people who are poor and downtrodden will be benefited again by this plan. The people who are living below the poverty line will be benefited.

When we talk of rural electrification I woud like to say that power generation is a capital-intensive industry. The cost of production is Rs. 3 crores per megawatt. You know the situation in the country. If the U.P. Government is not electrifying the villages, if the Madhya Pradesh Government is not electrifying the villages, if the Rajasthan Government is not electrifying the villages, if the Himachal Pradesh Government is not doing the work, am I responsible for it?

श्री महेश्वर सिंह : बस यही चार नजर आएंगी ।

SHRI KALP NATH RAI: Who is responsible for that? The Bihar Government is not electrifying the rural areas of that State. Am I responsible for that?

SHRI MAHESHWAR SINGH: What about Andhra Pradesh?

क्या मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश के भी फिगर्स रखेंगे . . . (**व्यवधान**) . . . आंध्र और कर्नाटक के फिगर्स यहां रखेंगे ?

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): Nobody is holding you responsible. It is the system, the whole system, which is doing this. No infrastructure has been created in all these States for rural electrification.

SHRI KALP NATH RAI: Let me reply. (Interruptioss). Let me reply one by one.

SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL (Uttar Pradesh): Sir, I am on a point of order. (Interruptions).

SHRI KALP NATH RAI: I am ready to reply one by one.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ भीम अफजल : मंत्री जी बोल रहे हैं तो मैं कैसे प्वाइंट आफ आर्डर उठाऊं । . . (**व्यवधान**) . . . मैं यह अर्ज कर रहा हूं तो यह महसूस कर रहा हूं कि मंत्री जी जब भी बोलते हैं तो अपनी खराबियों पर पर्दा डालने के लिए बेचारी ग्यारह महीने की सरकार के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं । कभी दूसरे स्टेट पर लगा देते हैं । मैं समझता हूं कि उनको अपनी विजारत तक सीमित रहकर बात करनी चाहिए . . (**व्यवधान**) . .

†[خبری محمد افضل عرف م۔ افضل: جب سبھی جی بول رہے ہیں تو میں کیسے پوائنٹ آف آرڈر اٹھاؤں ۔۔ "مداخلت" ۔۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ سبھی جی جب بھی بولتے ہیں تو اپنی خرابیوں پر پردہ ڈالنے کیلئے بے چاری گیارہ مہینہ کی سرکار کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کبھی دوسرے اسٹیٹ پر لگا دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی وزارت تک سیمت رہ کر بات کرنی چاہیے ۔

श्री मूल चन्द मीणा : जो खम्भे जल रहे थे वह सरकार के थे और तार काट दिए . . (**व्यवधान**)

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, I will point out only one fact to the hon. Minister. He has quoted to us the figures of the Seventh Five Year Plan. period, if I remember a right, none of these recent Government that he is referring to was responsible. There were other Governments. Mr. Minister, belonging to your party which were there.

SHRI KALP NATH RAI: I agree with you. I do not disagree. Sir, he has asked a relevant question. I agree. I have replied.

SHRI V. NARAYANASAMY: He has referred to these two years.

SHRI KALP NATH RAI: The hon. Member has asked the question Government was at the helm of affairs.

[**The Deputy Chairman** in the Chair]

I agree with Mr. Sinha. Today, the responsibility for rural electrification

†[ ]Transliteration in Arabic Script

[Shri Kalp Nath Rai]

is only of the State Governments which are ruling these areas. You are asking about the infrastructure. Today 1,450 MW is the capacity of Bihar. And what is the plant load factor? Twenty per cent, the lowest in India. Who is responsible? Am I responsible? You are an hon. Member of Parliament. You should try to know who is at fault. And capacity is there. The plant load factor is the lowest in Bihar. Then how can you get the power? How can the power be generated? How can the power be transmitted? If you don't have the system improvement, if you don't have the transmission lines, if you don't have 220 KV, 132 KV, 400 KV, 11 KV transmission lines, if you don't increase your plant load factor, you are responsible, that Government is responsible for that...

AN HON. MEMBER: Did electricity come to Bihar only during this Janata Dal Government or earlier during the Congress regime? What was the state of affairs there?

SHRI KALP NATH RAI: I am telling you...(*Interruptions*)... Listen. Today, the plant load factor in Bihar is the lowest in India and if anything is wrong, that is not the responsibility of our Government. Today what is the condition? You must admit it. Therefore, Madam Deputy Chairman, my Government is trying its level best to achieve the highest electrification and allocate maximum money through the Planning Commission to all States of the country. REC has done a commendable work and they are still doing a commendable work. As hon. Member Surjewalaji said, Haryana is hundred per cent electrified. If every Government works, hundred per cent electrification can take place in those States also...

Madam, one hon. Member asked me a question about Rajasthan. There are three cooperatives... (*Interruptions*). And whatever hon. Member Meenaji has said, the Government will look into the matter and will do whatever can be done for the electrification of all those villages and districts which have not been electrified. I will send a team of REC to Madhosingpur to verify whether the report submitted by the State Government is correct or not. If the report is not correct, my Government will make a special programme and allocate money. We will talk to the Chief Minister so that those villages and districts in the State can be electrified. Thank you very much.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. We have got three more things... ..

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): In this Golden Jubilee year of Quit India Movement is there any subsidy going to be given to the freedom fighters to electrify their houses? Madam, he has not answered my question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is any subsidy going to be given to the freedom fighters to electrify their houses?

SHRI KALP NATH RAI: Hon. Deputy Chairman, whatever has been done for freedom fighters has been done by Shrimati Indira Gandhi and by the Congress Governmet. Therefore, further subsidy will not be given.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): महोदय आपकी अनुमति से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बिहार के बारे में जो फिगर्स दी है और बिहार की जो स्थिति बतायी है, उससे जाहिर है कि बिहार की स्थिति बहत ही दयनीय है और इसलिए भी दयनीय है कि वहां जो केपेसिटी रही है उसके अनुसार केवल 20 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन हो रहा है। मैं इसको मद्देनजर रखते हुए केवल एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। आप स्वयं जब मानते हैं कि हमारे यहां बिहार की स्थिति सबसे खराब है, तो दूसरी जब होंगी, जहां 300 350, 450 मेधावाट खपत प्रति साल प्रति व्यक्ति होती है बिहार में 91.2

प्रतिशत, यह अभी प्राप्त हुई है । मैं जानना चाहूंगा कि हमारी थर्मल पॉवर की 11 योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास निलम्बित पड़ी हुई हैं ।

SHRI KALP NATH RAI: Madam Deputy Chairman, as hon. Member Shanker Dayalji knows—he was the man who raised the question of Koinkaro—that hydroelectric station is needed—because of his intervention I had made a sattement here that for the Koinkaro project Rs. 1,400 crores would be sanctioned by the Central Government. Now, the Cabinet has given approval and that is a boon to Bihar and that project has been sanctioned. But the project work has not yet started because Jharkhand people are coming and saying that until and unless you create a separate Jharkhand State they would not allow the work to be instituted.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: I am not asking only about Koel Karo project. I have mentioned about 11 projects which are under scrutiny and you have to give clearance to them.

SHRI KALP NATH RAI: Madam Deputy Chairman, as he has said, the projects have been sent to the Central Electricity Authority. All the projects have to be cleared by the Planning Commission; they have to be cleared by the PIB; they ave to be cleared by the Central Electricity Authority. Coal-hydro linkage has to be established and feasibility report has to be submitted by the State Government. The matters are under consideration. I will request you, respected Shankar Dayalji, that the boon for Bihar is Koel Karo project and I will sanction it. What Bihar needs today is hydel power project. In order to have a smoothly functioning grid Koel Karo project is a boon for Bihar Bengal and Orissa. I will request you to hold your hands. Kindy help to get that project instituted. Whatever help you need I will do for that project.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: You are controlling one faction of the Jharkhand Mukti Morcha.

SHRI KALP NATH RAI: Shankar Dayal Singhji, you tell me what I can do. If you need even my blood for the institution of that project I will do that.

AN HON. MEMBER: Madam, what is going on?

SHRI KALP NATH RAI: I love Bihar. I have tremendous love for the people of Bihar. I will request all the Members of Parliament... (*Interruptions*)... Bihar people are freedom fighters and they have done a lot for the country. I want the State to develop; I want the State to proper. The Cabinet has given approval for the biggest project of Bihar. Kindly ask the Chief Minister to executive that approved project. Then I shall clear the other projects pending before the Central Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, let us see how much the Minister loves Himachal.

श्री महेश्वर सिंह : उपसभापति महोदय, मैंने मूल प्रश्न के भाग "बी" में यह जानना चाहा था कि —

"(b) whether the Government are aware that electricity supply to the rural areas is very faulty, irregular and meagre."

उपसभापति : आप बोल चुके हैं, अभी क्या बोल रहे हैं ... (व्यवधान) नहीं-नहीं, अगर आप बोल चुके हैं तो बात खत्म हो गई ।

श्री महेश्वर सिंह : मैडम, जवाब नहीं आया, बोल तो चुका । मैंने यह डिस्कशन आपकी अनुमति से रेज किया था । जवाब नहीं आया तो सावल तो पूछना ही पड़ेगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That was the find reply. Shankar Dayal Singhji was allowed as a special case because he sat in the Chair for four houre. So, we have to give him some consideration.

श्री महेश्वर सिंह : मैडम, सिर्फ एक प्रश्न है कि जब ये लो वोल्टज की इम्प्रूवमेंट के लिए आर.ई.सी. के पास हिमाचल प्रदेश ने सिस्टम इंप्रूवमेंट स्कीम भेजी लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक मापदंडो में आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, अगर आप जनसंख्या को आधार रखेंगे और उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति को आधार नही रखेंगे तो कोई भी सिस्टम इंप्रूवमेंट स्कीम सफल नहीं हो सकती । तो क्या आप उसमें परिवर्तन करेंगे ? पहाडी प्रातों के लिए कोई छूट देंगे क्या ?

उपसभापति

That matter is closed now . चलिए खत्म हो गया । बिजली बहुत बन गई । मंत्री जी, आपने तो बड़े विस्तार से आधे घंटे का इतनी देर तक चलाया ।

श्री महेश्वर सिंह : यह इम्पोर्टेंट क्वश्चन है मैडम, । मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं ।

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): It is an important issue. The Minister has not answered.

SHRI MD. SALIM: Madam, it is an important question.

SHRI ASHIS SEN: He has got everything, but not this.

श्री महेश्वर सिंह : क्या आप उसमें कोई परिवर्तन करेंगे जहां जनसंख्या बहुल क्षेत्र नहीं है ।

SHRI KALAP NATH RAI: Madam Deputy Chairman, electricity is a concurrent subject. Seventy-five per cent of the power is generated by the State and 25 per cent by the Centre and this principle is applicable to all States.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, that matter is closed. Kalap Nathji, before the next session when we meet, I hope all the power problems of variouse States will be solved and you will come back here happily to give some good news to the Members and we will take half-an-hour to congratulate you. Thank you very much. Now, I have Kumari Selja sitting over here. Kumari Selja, bill for introduction, the Public Records Bill, 1992.

The Public Records Bill, 1992

THE DEPUTY CHAIRMAN IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE (KUMARI SELJA): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the management, administration and preservation of public records of the Central Government, Union territory Administrations, public secor uderakigs statutory tions, public sector undertakings, statutory bodies and corporations, commissions and committees constituted by the Central Government or a Union territory Administration and matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted

KUMARI SELJA: Madam, I introduce the Bill.